पिंकसिटी

गुजरात की कंपनी की पेचीदा शर्तों से आया अवरोध

अजमेर रोड में नए बस स्टैंड के विकास पर ब्रेक

महानगर संवाददाता

जयपुर। पीपीपी मोड पर अजमेर रोड पर नए रोडवेज बस स्टैंड के विकास में रुचि दिखाने वाली एजेंसी की शर्तों की पेचीदगियों के चलते रोडवेज प्रशासन के लिए आबादी क्षेत्र के बाहर स्टैंड बनाने के प्रयास अधूरे रह गए हैं। इधर सिंधी कैम्प केंद्रीय बस स्टैंड को मॉडल स्टैंड बनाने का कार्य पहले से ही मंथर गति से चल रहा है। करीब छह मह पूर्व अजमेर रोड के कमला नेहरू नगर पुलिया के समीप नए रोडवेज बस स्टैंड के विकास को लेकर संभावनाएं तलाशी गई थी। इसके लिए बकायदा जमीन भी चिह्नित की गई थी।

इससे एकबारगी यहां नए रोडवेज बस स्टैंड के निर्माण की उम्मीद जगी थी लेकिन इसके विकास में रुचि दिखाने वाली गुजरात की एक एजेंसी की ओर से रखी गई शर्तें रोडवेज प्रशासन को रास नहीं आई नतीजतन एक बारगी इसके निर्माण में अवरोध उत्पन्न हो गया। इसके बाद रोडवेज प्रशासन लगातार संबंधित एजेंसी को एप्रोच कर रहा है लेकिन ये अपनी शर्तों पर अड़ी हुई है। हालांकि परिवहन मंत्री लगातार संबंधित एजेंसी से संवाद

स्थापित कर शीघ्र ही नए स्टैंड के विकास किए जाने के संकेत दे रहे हैं। लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए निकट भविष्य में अजमेर रोड पर नए बस स्टैंड के विकास की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। गौरतलब है कि गुजरात की इस एजेंसी से जयपुर सहित प्रदेश के कई दूसरे शहरों में भी बस स्टैंड के विकास को लेकर रोडवेज प्रशासन की सहमति हुई थी।

इस रूट की बसों के लिए बनना था स्टैंड

अजमेर रोड के नए बस स्टैंड से अजमेर, अहमदाबाद, उदयपुर, जोधपुर सहित भीलवाड़ा, पाली जैसे शहरों की बसों का आवागमन निर्धारित किया जाना था। इस रूट की बसों के अजमेर रोड के नए बस स्टैंड में ठहरने से राजधानी में भीड़भाड़ वाले इलाकों में इनका आवागमन नहीं होता और इससे ट्रैफिक की समस्या से काफी हद तक निजात मिलती।

ट्रांसपोर्ट नगर बस स्टैंड पर नहीं मिल रहा यात्री भार

एक तरफ शहर के बाहरी इलाके में नए बस स्टैंड के विकास को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं वहीं ट्रांसपोर्ट नगर में पहले से स्थापित रोडवेज के बस स्टैंड में बसों को अपेक्षित यात्री भार नहीं मिल रहा है। इस बस स्टैंड में यात्री सुविधाओं की कमी के कारण भी यहां से आमजन दौसा, आगरा एवं इस रूट पर चलने वाली बसों में यात्रा करने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं।

बारिश के दौर में भी मंडराया पेयजल संकट का साया

महानगर संवाददाता

जयपुर। मानसून के दौर में भी राजधानी में पेयजल सप्लाई व्यवस्था के हाल-बेहाल है। जलदाय विभाग मौसम में आए बदलाव के बावजूद शहरवासियों की प्यास नहीं बुझा पा रहा है।

बीसलपुर योजना से पानी सप्लाई बढ़ाए जाने के जलदाय विभाग के बीते लंबे समय से किए जा रहे दावों की हकीकत शहर में गहराया पेयजल संकट बयां कर रहा है। ग्रीष्मऋतु में डिमांड के अनुरूप सप्लाई में जलदाय महकमा पूरी तरह नाकाम साबित हो चुका है और अब राजधानी का एक बड़ा इलाका अनियमित पेयजल सप्लाई की समस्या से ग्रस्त है। बहुत सी कॉलोनियों एवं गली-मोहल्लों में कम प्रेशर से पेयजल सप्लाई के कारण पर्याप्त पानी नसीब नहीं हो रहा है। ग्रीष्म ऋतु में ही नहीं मानसून के आगाज के बाद भी शहर में पेयजल किल्लत के कारण एक दर्जन से भी ज्यादा धरने एवं प्रदर्शन किए जा चुके हैं। मौजूदा समय में इंजीनियरिंग की तकनीकी खामियों के कारण परकोटा क्षेत्र लोगों को पूरे प्रेशर से पानी नहीं मिल रहा है। इसके बावजूद प्रभावित

कम प्रेशर से सप्लाई ने भी परेशानी बढ़ाई

इलाकों के एक्सईएन व एईएन फील्ड में जाकर प्रेशर जांचने व पाइपलाइनों के मिलाने में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं।

ऐसे में ज्यादा पानी होने के बावजूद लोगों को दिक्कत हो रही है। कई लोग पानी के लिए बूस्टर लगा रहे हैं। इससे पाइपलाइन के टेल एंड पर पानी नहीं पहुंच रहा है। शहर के कई जिन हिस्सों में पेयजल सप्लाई व्यवस्था सुचारू है वहां गंदे पानी की सप्लाई की भी शिकायतें आ रही हैं।

नए बिजली कनेक्शन के साथ बदले जाएंगे खराब मीटर

महानगर संवाददाता

जयपुर। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत जयपुर डिस्कॉम क्षेत्र के विद्युतीकृत गांवों में घरेलू बिजली कनेक्शन देने के लिए रविवार को प्रात: 10 से सांय 6 बजे तक शिविरों का आयोजन किया जाएगा। रविवार को जयपुर डिस्कॉम के 9 जिला क्षेत्रों में स्थित ग्राम पंचायत मुख्यालय, अटल सेवा केन्द्रों पर 62 शिविर लगेंगे। इनमें बीपीएल परिवारों को नि:शुल्क एवं अन्य आवासों को घरेलू बिजली कनेक्शन जारी करने के साथ ही खराब मीटरों को बदलने की व्यवस्था भी गई है।

जयपुर विद्युत वितरण निगम में झालावाड़ जिले में 7, कोटा में 4, बूंदी में 6, दौसा में 4, सवाई माधोपुर में 5, भरतपुर में 11, बारां में 2, टोंक में 7 व अलवर जिले में 16 शिविरों का आयोजन किया जाएगा।

पेयजल सप्लाई में अनियमित बिजली सप्लाई की मार

शहर में पेयजल सप्लाई व्यवस्था बिजली सप्लाई में बार-बार व्यवधान के कारण बुरी तरह प्रभावित हो रही है। मानसून की बारिश के चलते सप्लाई विद्युत तंत्र के गड़बड़ाने से इनके मेंटिनेंस को लेकर अलग-अलग इलाकों की बिजली सप्लाई बिना पूर्व सूचना के बाधित की जा रही है। ऐसी स्थिति में पेयजल सप्लाई के समय बिजली में व्यवधान परेशानी का कारण बनी हुई है। इसके अलावा दीपावली को लेकर डिस्कॉम की ओर से प्री-मेंटिनेंस कार्य भी चल रहा है, इस कारण भी बिजली बंद किए जाने से पेयजल सप्लाई में दिक्कतें आ रही है।

राजधानी की नई कॉलोनियों में रोशनी की आस अधूरी

एबी केबल की कमी से अटके सैकड़ों कनेक्शन

महानगर संवाददाता

जयपुर। राजधानी में सैकड़ों आवेदकों के बिजली कनेक्शन एबी केबल और पोल की कमी के चलते अटक गए हैं। इससे उपनगरीय क्षेत्रों एवं नव विकसित कॉलोनियों में बने नए मकानों में बिजली की आस अधूरी रह गई है। इससे शहरी क्षेत्र में आवेदन के कुछ दिन बाद ही कनेक्शन जारी करने के डिस्कॉम के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है।

पिछले दो महीनों से एबी केबल की आपूर्ति बुरी तरह लड़खड़ाई हुई है, नतीजतन रोशनी के पर्व दीपावली पर भी आवेदकों को बिजली कनेक्शन मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। हालांकि अधिकारी एबी केबल की शीघ्र आपूर्ति के संकेत दे रहे हैं। केबल के अलावा डिस्कॉम के पास विद्युत पोल का स्टॉक भी कम बताया जा रहा है। शहर के आमेर, अजमेर रोड, दिल्ली रोड सहित सांगानेर एवं अन्य उपनगरीय क्षेत्रों की दर्जनों कॉलोनियां के मकानों में बिजली कनेक्शन के इंतजार में अंधेरा छाया हुआ है जबकि इन क्षेत्रों के आवेदकों की ओर से निर्धारित शुल्क जमा करवाने के साथ ही जरूरी कागजी औपचारिकताएं भी पूरी कर ली गई हैं।

इसके बावजूद इनको कनेक्शन के लिए डिस्कॉम कार्यालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। एबी केबल की कमी से केवल कॉलोनियों एवं उपनगरीय क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि जयपुर डिस्कॉम के अंतर्गत आने वाले घनी आबादी के इलाकों में भी नए कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। हालत यह है कि बिजली कनेक्शन नहीं मिलने से बहुत से लोगों को नए मकानों में शिफ्टिंग में भी दिक्कतें आ रही हैं। नए कनेक्शन को लेकर निकटवर्ती इलाकों विद्युत तंत्र मौजूद होने के उपरांत भी एबी केबल उपलब्ध नहीं होने से कनेक्शन जारी नहीं किए जा रहे हैं।

एबी केबल उपलब्ध नहीं होने से कनेक्शन जारी नहीं किए जा रहे हैं

शहर में भी कनेक्शन को लेकर गांवों सी स्थिति

आमतौर पर शहर में आवेदन के बाद 15 दिन में बिजली कनेक्शन जारी हो जाता है लेकिन राजधानी में भी आवेदन के कई महिनों बाद कनेक्शन जारी नहीं होना डिस्कॉम की कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान लगा रहा है। हालांकि लम्बित आवेदकों की संख्या शहर में कम है लेकिन संसाधनों की कमी के चलते कनेक्शन जारी नहीं कर पाना डिस्कॉम के लिए भी परेशानी का कारण बन गया है।

निजी अस्पतालों में भी होगी स्वाइन फ्लू की नि:शुल्क जांच- उपचार

महानगर संवाददाता

जयपुर, 15 सितम्बर। स्वाइन फ्लू की स्थिति को देखते हुये इनडोर मरीजों की जांच एवं उपचार के लिए शहर के निजी अस्पताल जांच व उपचार कार्य जनहित में नि:शुल्क करने के लिए सहमत हो गए हैं। निजी अस्पतालों को स्वाइन फ्लू मरीजों के लिए अलग से आईसोलेशन वार्ड एवं आईसीयू में बेड्स रिजर्व रखने के लिए भी कहा गया है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कालीचरण सराफ की अध्यक्षता में शुक्रवार को शाम स्वास्थ्य भवन में निजी अस्पतालों, निजी लैब्स एवं दवा विक्रेताओं के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक में यह जानकारी दी गई। दवाईयों की दुकानों पर स्वाइन फ्लू की दवाओं की उपलब्धता एवं स्टाक की मात्रा की सूचना का बोर्ड लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं।

सराफ ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी निजी अस्पतालों को स्वाइन फ्लू के उपचार में काम में ली जा रही दवाइयां नि:शुल्क उपलब्ध करवाई जाएंगी। उन्होंने सभी निजी अस्पतालों को स्वाइन फ्लू पॉजिटिव मरीज की सूचना तत्काल स्वास्थ्य विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करने के लिए कहा है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी संबंधित क्षेत्रों में स्वाइन फ्लू के बारे में सर्वेक्षण कर संभावित रोगियों की जांच व उपचार सुनिश्चित करेंगे। चिकित्सा मंत्री ने बताया कि स्वाइन फ्लू के उपचार के लिए टेमीफ्लू औषधि के कैप्सूल, सीरप एवं वैक्सीन प्रदेश के सभी राजकीय चिकित्सालयों एवं प्रमुख निजी चिकित्सालयों पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में टेमी फ्लू औषधि की करीब 3 लाख 80 हजार कैप्सूल जिला चिकित्सालयों, सीएचसी, पीएचसी पर उपलब्ध हैं एवं आरएमएससीएल के सेंट्रल गोदाम में करीब 1 लाख 40 हजार कैप्सूल व बच्चों के 1 हजार 500 सीरप की बोटल स्टाक में उपलब्ध हैं। चिकित्सा मंत्री कहा कि निजी अस्पतालों व निजी लैब्स में स्वाइन फ्लू की नि:शुल्क जांच व उपचार सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया जा रहा है।